बिहार राज्य

बनाम

मैसर्स करम चंद थापर एंड ब्रदर्स लिमिटेड,

(एस॰के॰ दास, जे॰एल॰ कपूर, एम॰ हिदयातुल्लाह,

जे॰सी॰ शाह एवं टी॰एल॰ वेंकटरमन अय्यर, जे॰जे॰)

स्टाम्प–अवार्ड–मध्यस्थ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, पार्टियों और अदालत को पुरस्कार (निर्णय) की प्रतियां भेजना–बिना टिकट वाले पुरस्कार (निर्णय) की मान्यता–उस पर पारित डिक्री–वैधता–भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2), एस. 35.

मध्यस्थता समझौते को संदर्भित करने के लिए मध्यस्थता–राज्यपाल की ओर से विशेष रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादन–प्राधिकरण की आवश्यकताएं–भारत सरकार अधिनियम, 1935 (25 और 26 जिओ. 5 अध्याय 42), एस. 175(3).

सरकार के लिए किए गए निर्माण कार्यों के संबंध में कंपनी को देय राशि के बिलों को लेकर प्रतिवादी कंपनी और बिहार सरकार के बीच विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। मध्यस्थता को संदर्भित करने का समझौता राज्यपाल की ओर से एक कार्यकारी अभियंता 'एल' द्वारा निष्पादित किया गया था, जिसे विशेष रूप से सरकार के सचिव द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया था। मध्यस्थ ने अपना निर्णय दिया और उसकी प्रतियां पार्टियों को भेज दीं। प्रतिवादी ने पंचाट अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत पुरस्कार (निर्णय) के संदर्भ में डिक्री के लिए न्यायालय में आवेदन किया। राज्य ने इस पर आपत्ति दर्ज की और मामले को एक मुकदमे के रूप में दर्ज किया गया। जब मुकदमा लंबित था, तो मध्यस्थ ने अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार दायर करने के लिए अपने द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पुरस्कार (निर्णय) की एक प्रति अदालत को भेजी थी, और उसकी प्राप्ति पर प्रतिवादी ने धारा के तहत अपेक्षित स्टांप शुल्क के भुगतान पर इसे मान्य किया था। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के 35। अपीलकर्ता, बिहार राज्य ने तर्क दिया कि पुरस्कार (निर्णय) के आधार पर इस आधार पर कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है (1) कि मध्यस्थता के संदर्भ के लिए समझौता आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है। एस.। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 175(3), चूँकि 1 अप्रैल 1937 को बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना के तहत ऐसा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। 175(3)य और (2) कि अदालत के समक्ष लिखत एक प्रमाणित प्रति थी और धारा के तहत। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के 35 के अनुसार, एक प्रति को मान्य नहीं किया जा सकता या उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। आयोजित, वह एस. भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 175(3), किस प्राधिकरण में कोई विशेष तरीका निर्धारित नहीं करता है प्रदान किया जाना चाहिए और जहां प्राधिकार प्रदान किया गया है। किसी भी व्यक्ति पर तदर्थ, अनुभाग की आवश्यकताएं होनी चाहिए संतुष्ट माना जाता है.

{1962}

1961

बिहार राज्य

बनाम

करम चन्द थापर एवं ब्रादर्स लिमिटेड

आगे, यह माना गया कि मध्यस्थ द्वारा अदालत को भेजा गया पुरस्कार (निर्णय) मूल था, न कि फैसले की प्रति और एस0के0 प्रावधानों को लागू करके। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के 35 के अनुसार इसे प्रभावी ढंग से मान्य किया गया।

बोब्बिली के राजा बनाम इनुगांती चीन सीतारमासामी गारू, (1899) एल०आर०26, आई०ए०262, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 1959 की सिविल अपील संख्या 209।

1953 की विविध अपील संख्या 367 में पटना उच्च न्यायालय के 5 अक्टूबर, 1956 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील।

अपीलकर्ता की ओर से एल०के०झा और आर०सी०प्रसाद। एम०सी० सीतलवाड, भारत के अटॉर्नी–जनरल, एन०डी० और पी०के० मुखर्जी, उत्तरदाताओं के लिए।

1961, 7 अप्रैल, न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

वेंकटरामा अय्यर, जे.–

वेंकटराम अय्यर जे०– यह मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत एक अपील में पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील है। अपीलकर्ता बिहार राज्य है, और उत्तरदाता भारतीय कंपनियों के तहत पंजीकृत कंपनी हैं अधिनियम, निर्माण ठेकेदारों के रूप में व्यवसाय करना। उन्होंने रांची में हवाई अड्डे, हैंगरेट्स, इमारतों, दुकानों और अन्य कार्यों के निर्माण के लिए तीन अनुबंधों में प्रवेश किया, उनमें से पहला 1942 का अनुबंध संख्या 21 दिनांक 5 नवंबर, 1942 था, और अन्य दो अनुबंध संख्या 6 और 8 थे। दिनांक 5 अप्रैल, 1943। उपरोक्त कार्य पूरा होने के बाद, बिलों को लेकर पार्टियों के बीच विवाद पैदा हो गए और अंततः 6 फरवरी, 1948 के एक समझौते के द्वारा, उन्हें एक कर्नल ए०डब्ल्यू०एस० स्मिथ की मध्यस्थता के लिए भेजा गया। मध्यस्थ ने 4 जून, 1948 को अपना फैसला सुनाया और उसकी एक प्रति पक्षों को भेज दी। इसके बाद उत्तरदाताओं ने एसएस के तहत एक याचिका दायर की। पुरस्कार (निर्णय) के संदर्भ में डिक्री के लिए भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 17 और 20। अपीलकर्ता ने उस पर आपत्तियां दायर कीं, और याचिका को 1951 के टाइटल सूट नंबर 53 के रूप में पंजीकृत किया गया था। जबकि यह मुकदमा लंबित था, मध्यस्थ जो इस बीच हांगकांग के लिए रवाना हो गया था, ने अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की।

1961

बिहार राज्य

बनाम

करम चंद थापर एंड ब्रदर्स लिमिटेड

रांची, जिसके समक्ष मुकदमा लंबित था, अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार दायर करने के लिए उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पुरस्कार (निर्णय) की एक प्रति। के तहत न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये। अधिनियम के 14(2) और, उसके उत्तर में, अपीलकर्ता ने विभिन्न आधारों पर पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया। इस पर प्रतिवादियों ने अपना जवाबी बयान दाखिल किया। इस आवेदन के मद्देनजर, उत्तरदाताओं ने एसएस के तहत अपनी याचिका पर जोर नहीं दिया। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 और 20, जिसे परिणामस्वरूप खारिज कर दिया गया था, और मध्यस्थ से पुरस्कार (निर्णय) की प्राप्ति के साथ शुरू हुई कार्यवाही 1951 के टाइटल सूट नंबर 53 के रूप में जारी रखी गई थी। एक विस्तृत परीक्षण के बाद, अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायाधीश, रांची, पुरस्कार (निर्णय) के संदर्भ में एक डिक्री पारित की, सिवाय उस हिस्से के जिसे उन्होंने दावे से अधिक माना। अपीलकर्ता ने इस मामले को पटना उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने अधीनस्थ न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि की, लेकिन कला के तहत एक प्रमाण पत्र प्रदान किया। संविधान के 132 और 133(1), और इसलिए यह अपील। यद्यपि पार्टियों के बीच विवाद नीचे की अदालतों में एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, हमारे सामने, यह दो प्रश्नों तक ही सीमित था– क्या सरकार पर बाध्यकारी मध्यस्थता के संदर्भ में एक वैध समझौता था और क्या बिना मुहर लगी डिक्री पारित की जा सकती थी। न्यायालय में दाखिल फैसले की प्रति। पहले प्रश्न पर, अपीलकर्ता का तर्क है कि मध्यस्थता के संदर्भ के लिए समझौता एस की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 का 175(3), जो प्रासंगिक तिथि पर लागू संवैधानिक प्रावधान था, और इसलिए यह शून्य है, कि उस पर स्थापित कार्यवाही में पारित पुरस्कार (निर्णय) अमान्य है और कोई डिक्री नहीं होनी चाहिए उसके संदर्भ में पारित किया गया। धारा 175(3) इस प्रकार हैः–

"संघीय रेलवे प्राधिकरण के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, फेडरेशन या प्रांत के कार्यकारी प्राधिकरण के अभ्यास में किए गए सभी अनुबंध गवर्नर–जनरल, या द्वारा किए गए माने जाएंगे प्रांत के राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, और ऐसे सभी अनुबंध और संपत्ति के सभी आश्वासन उस प्राधिकार के प्रयोग में किए गए कार्यों को गवर्नर–जनरल या गवर्नर की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसे तरीके से निष्पादित किया जाएगा जैसा वह निर्देशित या अधिकृत कर सकता है।

1961

बिहार राज्य

बनाम

करम चंद थापर एंड ब्रदर्स लिमिटेड

वेंकटरामा अय्यर जे.

इस धारा के तहत, किसी प्रांत के गवर्नर द्वारा किए गए अनुबंध को तीन शर्तों को पूरा करना होगा। इसे राज्यपाल द्वारा बनाया जाना व्यक्त किया जाना चाहिए। इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। और निष्पादन ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसे तरीके से होना चाहिए जैसा कि राज्यपाल निर्देशित या अधिकृत कर सकते हैं। अब हमें यह जांचना है कि क्या 6 फरवरी 1948 को मध्यस्थता को संदर्भित करने वाला समझौता उपरोक्त शर्तों को पूरा करता है। यह बिहार के राज्यपाल और प्रतिवादियों के बीच बनी होने की संभावना है. यह वाई o केo लाल, कार्यकारी अभियंता, रांची डिवीजन और उत्तरदाताओं द्वारा निष्पादित एक औपचारिक दस्तावेज भी है। इसलिए विचार करने के लिए एकमात्र बिंदु यह है कि क्या कार्यकारी अभियंता एक ऐसा व्यक्ति था जिसे निर्देशित या अधिकृत किया गया था। राज्यपाल को प्रश्नगत समझौते को क्रियान्वित करना होगा। अपीलकर्ता का तर्क है कि वह बिहार सरकार द्वारा जारी 1 अप्रैल, 1937 की अधिसूचना पर अपने तर्क का समर्थन नहीं करता था। वह अधिसूचना, जहाँ तक है सामग्री, इस प्रकार हैः

"भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 175 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, सभी मौजूदा आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, निर्देश देने के लिए प्रसन्न हैं कि उसकी ओर से निम्नलिखित वर्गों के कार्यों, अनुबंधों और अन्य दस्तावेजों को निम्नानुसार निष्पादित किया जा सकता हैः–

ए. **लोक निर्माण विभाग के मामले में (विभागीय आदेशों द्वारा निर्धारित किसी सीमा के अधीन)।**		
2. इमारतों, पुलों, सड़कों, नहरों, टैंकों, जलाशयों, गोदी और बंदरगाहों और तटबंधों से जुड़े सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन से संबंधित सभी उपकरण, और संबंधित उपकरण भी जल कार्यों के निर्माण, सीवेज कार्यों, मशीनरी के निर्माण और कोयला खदानों के कामकाज के लिए।		सरकार के सचिवों, मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, प्रभागीय अधिकारियों, उप–विभागीय अधिकारियों, सहायक या सहायक कार्यकारी इंजीनियर द्वारा, और इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर द्वारा । सचिवों एवं संयुक्त सचिवों द्वारा।

1961

बिहार राज्य

बनाम

करमचंद थापर एवं ब्रादर्स लिमिटेड

वेंकटरामा अय्यर जे.

12. उन सरकार के अलावा किसी भी मामले से संबंधित सभी कार्य और दस्तावेज। शीर्ष 1 से 11 में निर्दिष्ट। नीचे की अदालतों में इस बात पर चर्चा हुई कि क्या वर्तमान समझौता आइटम 2 या आइटम 12 के अंतर्गत आता है। यदि समझौते को कार्यों के निष्पादन से संबंधित एक साधन के रूप में माना जा सकता है, तो यह आइटम 2 के अंतर्गत आएगा, और कार्यकारी अभियंता इस अनुबंध में प्रवेश करने के लिए इस अधिसूचना के तहत अधिकृत व्यक्ति होगा, लेकिन यदि यह उस मद के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसे प्रविष्टि 12 के अंतर्गत आना चाहिए, जिस स्थिति में वह समझौते को निष्पादित करने के लिए सक्षम नहीं होगा। नीचे दी गई दोनों अदालतों ने माना है कि मध्यस्थता को संदर्भित करने वाला समझौता कार्यों के निष्पादन से संबंधित नहीं था क्योंकि वह पूरा हो चुका था और विवाद केवल बिलों के भुगतान से संबंधित था, और इसके अलावा मध्यस्थता समझौते की आवश्यक विशेषता संविधान थी। एक निजी न्यायाधिकरण है और इसलिए इसे आइटम 2 के भीतर नहीं लाया जा सका और तदनुसार यह आइटम 12 के अंतर्गत आता है। लेकिन उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों की यह भी राय थी कि कार्यकारी अभियंता वाई°के° लाल को वास्तव में निर्दिष्ट किया गया था–मध्यस्थता समझौते को निष्पादित करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत, और वह एस के उद्देश्य के लिए पर्याप्त था। 175(3).अपीलकर्ता इस निष्कर्ष की सत्यता पर सवाल उठाता है और तर्क देता है कि यह रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं है। इसलिए, इस बिंदु से संबंधित पत्राचार का कुछ विस्तार से उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। 26 जुलाई, 1947 को सरकार के सचिव श्री मुरेल ने कर्नल स्मिथ को इस प्रकार लिखाः

"मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि बिहार सरकार आपको रांची–जॉब 108 में हिनू एयरोड्रोम के निर्माण के संबंध में मेसर्स करम चंद थापर एंड ब्रदर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दावे के निपटारे के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव करती है। ....यदि आप ऐसा करने के लिए सहमत हैं

1961

बिहार राज्य

बनाम

थापर एंड ब्रदर्स लिमिटेड

वेंकटरामा अय्यर जे०

कार्य,.....मध्यस्थ आदि की नियुक्ति की स्वीकृति के आवश्यक प्रपत्र कृपया बिहार सरकार और ठेकेदार द्वारा पूरा करने के लिए इस विभाग को भेज दिए जाएं।"

इस पर कर्नल स्मिथ ने मध्यस्थ के रूप में कार्य करने पर सहमति व्यक्त करते हुए उत्तर भेजा। उस पत्र में उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मध्यस्थता की अनुमति देने के लिए पार्टियों के बीच अनुबंध में उचित संशोधन किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीएल के तहत अनुबंध के 23, पार्टियों के बीच सभी विवादों को अधीक्षण अभियंता को भेजा जाना था जिसका निर्णय अंतिम होना था, और यदि सुझाव के अनुसार संशोधन किया गया होता, तो मध्यस्थता खंड मूल अनुबंध का हिस्सा बन जाता और वहाँ होता वर्तमान विवाद का कोई कारण नहीं है। समझौते में संशोधन के लिए उपरोक्त सुझाव का उल्लेख करते हुए, सचिव श्री मुरेल ने 5 सितंबर, 1947 को कर्नल स्मिथ को लिखा कि कानूनी अनुस्मारक की राय लेनी होगी। 19 जनवरी, 1948 को, कर्नल स्मिथ ने सचिव को लिखा कि वह मध्यस्थ के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार हैं और फिर से चाहते हैं कि अनुबंध में संशोधन किया जाए ताकि मध्यस्थता का प्रावधान किया जा सके। 27 जनवरी, 1948 को, सरकार के सचिव ने कर्नल स्मिथ को सूचित किया कि लीगल रिमेंबरेंसर से राय प्राप्त हुई है कि मध्यस्थता के लिए एक समझौते को मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित किया जाना चाहिए और एक मसौदा समझौता (प्रति संलग्न) तदनुसार तैयार किया गया है और इसे यथाशीघ्र निष्पादित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उसी तिथि को, कार्यकारी अभियंता ने उत्तरदाताओं को इस प्रकार लिखाः–

"तब से सरकार द्वारा उपरोक्त के संबंध में आपके दावों को 1940 के मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयोजित मध्यस्थता के माध्यम से निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया आवश्यक समझौते को निष्पादित करने के लिए तुरंत मंडल कार्यालय में उपस्थित हों उद्देश्य।"

इस पत्र के अनुसरण में, प्रतिवादी 6 फरवरी 1948 के समझौते के निष्पादन में कार्यकारी अभियंता के साथ शामिल हुए।

1961

बिहार राज्य

बनाम

थापर एंड ब्रदर्स लिमिटेड

वेंकटरामा अय्यर जे०

मध्यस्थता के लिए विवाद. 25 फरवरी, 1948 को, सचिव ने मध्यस्थ को सूचित किया कि सरकारी वकील के परामर्श से समझौते के मसौदे में थोड़ा संशोधन किया गया है, और उन्होंने कार्यकारी अभियंता को यह भी लिखा कि समझौते में कुछ औपचारिक सुधार किए जाने चाहिए और दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। और वैसा ही किया गया।

पत्राचार को ध्यान से पढ़ने के बाद, हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों से सहमत हैं कि कार्यकारी अभियंता को मध्यस्थता के संदर्भ के लिए समझौते को निष्पादित करने के लिए अपने सचिव के माध्यम से राज्यपाल द्वारा अधिकृत किया गया था। यह देखा जाएगा कि यह सचिव ही थे। जिन्होंने शुरुआत से ही मध्यस्थता की व्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वह पूरे समय सरकार के नाम पर और उसकी ओर से बोल रहे थे और उन्होंने "निर्देशानुसार" ऐसा किया। मध्यस्थता का विषय–वस्तु एक दावा था जिसका संबंध सरकार से था। सीएल में संशोधन का प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है। मूल अनुबंध के 23 में मध्यस्थता को शामिल करने से पता चलता है कि पार्टियों का इरादा मध्यस्थता के लिए समझौते को उस अनुबंध के भाग और पार्सल के रूप में मानना था। समझौता निष्पादित होने के बाद भी, सचिव ने इस आधार पर समझौते में सुधार और संशोधन किए कि यह सरकार थी जो उसमें एक पक्ष थी। इस सब से यह निष्कर्ष, हमारे निर्णय में, अपरिवर्तनीय है कि वाई.के. लाल, कार्यकारी अभियंता को दिनांकित समझौते को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया था। फरवरी 6, 1948।

यह सुझाव दिया गया कि सचिव संभवतः एक गलत धारणा के तहत काम कर रहे थे कि मध्यस्थता को संदर्भित करने वाला समझौता आइटम 2 के अंतर्गत आता है और उस गलत धारणा के तहत कार्य करते हुए उन्होंने वाई०के० लाल को समझौते को निष्पादित करने का निर्देश दिया। यदि ऐसा था भी, तो इससे स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सचिव का निस्संदेह इरादा था कि वाई ० के० लाल को समझौते को निष्पादित करना चाहिए और धारा के तहत बस इतना ही आवश्यक है। 175(3) अपीलकर्ता की ओर से आगे यह तर्क दिया गया कि औपचारिक चरित्र की एक सरकारी अधिसूचना है,

1961

बिहार राज्य

बनाम

थापर एंड ब्रदर्स लिमिटेड

वेंकटरामा अय्यर जे०

हमें इसके बाहर यात्रा नहीं करनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति में अधिकार नहीं ढूंढना चाहिए जो इसके तहत अधिकृत नहीं है। लेकिन एस. 175(3) कोई विशेष तरीका निर्धारित नहीं करता है जिसमें अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। आम तौर पर, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा सम्मान आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा होगा, लेकिन अनुभाग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को तदर्थ प्राधिकरण प्रदान करने से रोकता हो, और जब यह स्थापित हो जाता है, तो अनुभाग की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए संतुष्ट होना। परिणाम में, हम मानते हैं कि 6 फरवरी 1948 के समझौते को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया था जिसे राज्यपाल द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया था, और परिणामस्वरूप मध्यस्थता का एक वैध संदर्भ था।

अगला तर्क यह दिया गया कि चूंकि अदालत में पुरस्कार (निर्णय) की प्रति पर मुहर नहीं थी, इसलिए उस पर कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी। तथ्य यह है कि मध्यस्थ ने प्रत्येक पक्ष को अपने द्वारा हस्ताक्षरित निर्णय की एक प्रति भेजी और उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक तीसरी प्रति भी अदालत को भेजी गई। पुरस्कार (निर्णय) की जो प्रति सरकार को भेजी गई थी, ऐसा प्रतीत होता है कि उस पर अपर्याप्त मुहर लगाई गई थी। यदि इसे अदालत में पेश किया गया होता, तो इसे धारा के तहत कमी और जुर्माने के भुगतान पर मान्य किया जा सकता था। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का 35। लेकिन सरकार इसे प्रस्तुत करने में विफल रही है। कहा जाता है कि पुरस्कार की प्रति जो उत्तरदाताओं को भेजी गई थी, पुलिस ने अन्य कागजात के साथ जब्त कर ली है और अब उपलब्ध नहीं है। जब तीसरी प्रति अदालत में प्राप्त हुई, तो उत्तरदाताओं ने धारा के तहत अपेक्षित स्टांप शुल्क का भुगतान किया। स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 और इसे मान्य किया गया था। अब अपीलकर्ता का तर्क यह है कि वास्तव में अदालत के समक्ष दस्तावेज, जैसा कि इसका तात्पर्य है, "एक प्रमाणित प्रति" है, और वह धारा के तहत है। स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 में केवल मूल का ही सत्यापन किया जा सकता है, जब यह बिना स्टांप वाला या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित हो, अदालत में दस्तावेज जो एक प्रति है उसे मान्य नहीं किया जा सकता है और "उस पर कार्रवाई" नहीं की जा सकती है और इसके परिणामस्वरूप कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। उस पर. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी उपकरण की प्रतिलिपि को मान्य नहीं किया जा सकता है। यह बोब्बिली के राजा बनाम इनुगांती चीन सीतारमासामी गारू (1) में आयोजित किया गया था, जहां यह देखा गया थाः

(1) (1899) एल.आर. 26 आई.ए. 262.

1961

बिहार राज्य

बनाम

थापर एंड ब्रदर्स लिमिटेड

वेंकटरामा अय्यर जे॰

"इस धारा (धारा 35) के प्रावधान जो दंड के भुगतान पर किसी दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देते हैं, तब कोई लागू नहीं होता जब मूल दस्तावेज, जिस पर मुहर नहीं लगी थी या अपर्याप्त रूप से मुहर लगी थी, का उत्पादन नहीं किया गया हैय और, तदनुसार, द्वितीयक इसकी सामग्री का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। अन्यथा धारण करना अधिनियम में एक प्रावधान जोड़ना होगा जो इसमें शामिल नहीं है। दंड का भुगतान द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार्य नहीं बनाएगा, क्योंकि स्टांप कानून के तहत जुर्माना केवल बिना मुहर लगे पर लगाया जा सकता है। या पर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेज वास्तव में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और वह कानून खोए हुए दस्तावेजों पर कोई जुर्माना लगाने का प्रावधान नहीं करता है।

इसलिए सवाल यह है कि क्या मध्यस्थ द्वारा अदालत को भेजा गया फैसला मूल दस्तावेज है या उसकी प्रतिलिपि है। हमारी राय में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह मूल है, पुरस्कार (निर्णय) की प्रतिलिपि नहीं। मध्यस्थ ने जो किया वह यह था कि निर्णय को तीन प्रतियों में तैयार किया, उन सभी पर हस्ताक्षर किए और एक को पार्टी को और तीसरे को अदालत को भेजा। यह एक मूल उपकरण होगा, और उस पर दिखाई देने वाले शब्द, "प्रमाणित प्रति" एक गलत वर्णन है और उपकरण के वास्तविक चरित्र को बदलने का प्रभाव नहीं डाल सकता है। अपीलकर्ता के इस तर्क में भी कोई दम नहीं है। परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है।

अपील खारिज.